

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

होने और इस प्रकार सरकारी कोष को घसीमित हानि पहुँचने के अनेकों समाचार देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में मिले हैं।

पिछले वर्ष पीलीभीत के पूरनपुर स्थान पर 1 करोड़ रुपये मूल्य के गेहूँ को भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले एवं असुरक्षित स्थान पर रखने व इस कारण उसके बरबाद हो जाने का समाचार मिला था। हरियाणा व पंजाब में भी गेहूँ आदि की भंडारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण भारतीय खाद्य निगम करोड़ों रुपये की बरबादी का उत्तरदायी ठहराया गया। किसी किसी स्थान पर तो तीन चार वर्ष तक अन्न पड़ा रहने से बरबाद हो गया।

अभी हाल में पंजाब व विशेष रूप से चंडीगढ़ में करोड़ों रुपये मूल्य के भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए गेहूँ के भीग कर बरबाद हो जाने के समाचार प्रकाशित हुए हैं।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीलीभीत जिले के बीसलपुर कस्बे में ३० प्र० सरकार द्वारा खरीदा हुआ 1979-80 का 35 हजार बोरी चावल अक्तूबर, 1980 में भारतीय खाद्य निगम के क्वालिटी इन्स्पेक्टर को लिखित रूप में सौंप दिया गया था जिसका अनुमानित मूल्य 55 लाख रुपया था जिसमें से उक्त क्वालिटी इन्स्पेक्टर ने लगभग 8 हजार बोरी बाहर भेज दी तथा 45 लाख रुपये मूल्य की 27 हजार बोरियां अभी भी तब से वहीं रखी बरबाद हो रही हैं। ये बोरियां प्राइवेट चावल मिलों के जीर्ण-शीर्ण व अनुपयुक्त भण्डार गृहों में रखी हुई हैं जिन पर भारतीय खाद्य निगम का ताला पड़ा हुआ है। लगभग तीन वर्ष हो गए हैं, न तो चावल अन्यत्र भेजा गया है, न ही गोशामों

का किराया अदा किया गया है। चावल की बरबादी हो रही है। सरकार से मेरी मांग है कि वह भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण व्यवस्था को ठीक करे और अन्न की बरबादी को रोके।

(vii) NEED TO STEP UP MILK PRODUCTION IN THE COUNTRY.

श्री वी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एतद्द्वारा माननीय कृषि मंत्री का ध्यान देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता में लगातार होते हुए ह्रास की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आजादी के पूर्व देश में प्रति व्यक्ति लगभग 150 ग्राम दूध उपलब्ध था। धीरे-धीरे घट कर आज यह मात्रा मात्र 100 ग्राम रह गई है। दूध के इस अभाव के कारण उसके मूल्यों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है और आज संसार में संभवतः दूध भारत में सबसे महंगा है। दूध की कमी को दूर करने के लिए उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के स्थान पर सरकार स्किम्ड मिल्क पाउडर तथा बटर आयात के आयात पर अधिक ध्यान दे रही है। 1970 से बहुचर्चित आपरेशन फ्लूड प्रोजेक्ट असफल हो रहा है। स्वयं गुजरात में लगातार दुग्ध उत्पादन में ह्रास होता जा रहा है। जहां 1977-78 में वहां 2.188 मिलियन टन दूध उत्पन्न हुआ था, 1978-79 में वह घट कर 2.165 मिलियन टन हो गया और 1979-80 में और घट कर 2.115 मिलियन टन हो गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्धोत्पादन एवं गांव में ही उसका क्रय करने की सुव्यवस्थित योजना का अभाव दुग्ध उपलब्धि में बड़ा बाधक हो रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास परिषद् एवं भारतीय डेयरी निगम स्किम्ड मिल्क पाउडर के आयात पर अधिक ध्यान

दे रहे हैं। यह वही बात हो रही है, जैसे प्रारम्भ में केन्द्रीय सरकार ने खाद्यान्न के आयात की ओर अधिक ध्यान दिया और उत्पादन की ओर कम। दूध अभाव एवं अप्रत्याशित रूप से उसके बढ़ते हुए मूल्य के कारण जन-सामान्य के लिए मृग-मरोचिका बनता जा रहा है। भोजन में इसकी क्या महत्ता है और मानव जीवन के लिए इस की कितनी आवश्यकता है, यह कहने की जरूरत नहीं। आज देश में दूध भोजन नहीं औषधि बन चुका है।

अतएव मैं माननीय कृषि मंत्री जी से साग्रह अनुरोध करूंगा कि दुग्ध चूर्ण के आयात के सहारे न रह कर देश में दुग्धोत्पादन के लिए प्रभावकारी कार्यक्रम चलाएं। इसके लिए सभी आवश्यक कारकों के विकास के लिए वरीयता के आधार पर कदम उठाए जाने चाहिए।

(viii) MAHARASHTRA-KARNATAKA BORDER DISPUTE

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Women from Maharashtra-Karnataka border areas have come to Delhi, to stage a peaceful 'dharna' before the Parliament, to focus the attention of the Government and the people on the need to settle the long pending Maharashtra-Karnataka border dispute, both in the interest of Maharashtra as well as Karnataka, so that people in the border areas who have remained deeply involved in the border situation for more than two decades, can get the opportunity to join the mainstream of national political life and developmental activities.

The women demonstrators will be presenting a memorandum to the Speaker of the Lok Sabha and also to the Prime Minister.

In the Fifth Lok Sabha, the Prime Minister and the Union Home

Minister had assured that the pending border dispute would be settled before the elections to the Sixth Lok Sabha.

In the Sixth Lok Sabha, the Union Home Minister had already fixed a joint meeting with the Chief Ministers of Maharashtra and Karnataka, to hammer out a solution. However, before the meeting could be held, the Lok Sabha was dissolved.

In the Seventh Lok Sabha, the issue was raised a number of times. The Maharashtra Ekikaran Samiti's MLAs from the Karnataka Assembly, elected from the Maharashtra-Karnataka border areas, had met the then Home Minister and suggested to him that he should urge the Chief Ministers of Maharashtra and Karnataka to leave the solution to the Central Government, and then the Centre should hammer out a solution. The Home Minister had accepted the suggestion.

Unfortunately, despite peoples verdict unequivocally expressed through Assembly and local body elections since 1957, the border issue has remained still unresolved. It may be recalled that these elections were fought on the question of settling the border dispute by treating village as a unit, and by taking into account linguistic majority, geographical contiguity and people's wishes democratically expressed.

Against the background of all these developments, I request, the Home Minister to make a statement in the House indicating Government's determination to settle the Maharashtra-Karnataka border dispute in a time-bound manner.

(ix) NEED TO PROVIDE ASSISTANCE TO TRIPURA GOVERNMENT TO MEET THE SITUATION CREATED BY HEAVY FLOODS.

SHRI AJOY BISWAS (Tripura West) : Sir, due to continuous rains